(ख) क्या यह सच है कि गत 15 वर्षों में देश में एकाधिकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है ;

(ग) यदि हां, तो इस के लिये सरकार की नीतियां तथा उनकी क्रियान्वित कहां तक जिम्मेदार हैं ; और

(घ) ग्रामों में उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया विधेयक की ओर, जो इस सदन के समक्ष अनिर्णीत है, ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) और (ग) . एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(घ) सरकार द्वारा, ग्रामो में उद्योग स्थापित करने के लिये बनाई गई योजना दो प्रकार की है :—

(1) ग्राम उद्योग, जिनके लिये खादी आयोग द्वारा, सहायता दी जाती है ;

(2) ग्रामीण उद्योग विकास प्रोग्राम ।

(1) के अन्तर्गत, खादी आयोग, खादी के विकास तथा अन्य अनेक ग्राम उद्योगों के लिये सहायता देता है जैसे ग्राम का तेल, धानों का हाथ से कूटा जाना, ग्रामीण चमड़ा, शहद की मक्खी पालना, गुड़ तथा खांडसारी, ताड़ का गुड़, मिट्टी के बर्तन, ग्रामीण बढ़ई तथा लोहार का काम, हाथ के दियासलाई के बक्से, हाथ मे कागज बनाना, अखाद्य तेल व साबुन इत्यादि ।

(2) की बाबत, उन ग्रामों के विकास तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये, जो ग्रामीण उद्योग विकास क्षेत्र मे आ गये हैं, लघु उपक्रमों की व्यवस्था करके तथा शिल्पियों को आर्थिक सहायता जैसे जमा सुविधायें, उन्नत औजार, प्रशिक्षण सुविधाओं का संगठन, बाजार सहायता, सामान सुविधायें इत्यादि देने के पग उठाये जा रहे हैं ।

Changes in Industrial Policy Resolution

*602. SHRI PREM CHAND VERMA. Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is proposed to bring about some changes in the Industrial Policy Resolution;

(b) whether it is a fact that he gave a hint about this about two months ago; and

(c) if so, when the changes are to be formally introduced and what is the nature of these changes?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (c). The present Industrial Policy was set out by Government in its Industrial Policy Resolution, 1956. In view of the subsequent development in various fields, the policy is being re-assessed especially with regard to the future of the public sector, the utilisation of credit from public financial institutions, the regulation of industries with a view to preventing concentration of economic power, the dispersal of industries in different regions and the development of small scale industries in the context of the strategy for accelerated industrial growth. The Industrial Licensing Policy Inquiry Committee, Administrative Reforms Commission and the Planning Commission have also made a number of recommendations relating to industrial policy. All these matters are currently under examination.

(b) It was mentioned that the findings and recommendations of Industrial Licensing Policy Inquiry Committee might call for some changes in the Industrial Policy Resolution of 1956.